भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

07.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2348 का उत्तर

नांगल बांध-तलवाड़ा-मुकेरियां रेल लाइन खंडों का निर्माण

2348. श्री हर्ष महाजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नांगल बांध-तलवाड़ा-मुकेरियां नई रेल लाइन परियोजना के दौलतपुर चौक-करटोली-तलवाड़ा तथा तलवाड़ा-मुकेरियां खंडों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें पुलों, वायाडक्टों तथा स्टेशन भवनों के पूर्ण हुए निर्माण कार्य का प्रतिशत भी शामिल है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा इन खंडों के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित तथा जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष खंडों के पूर्ण होने तथा चालू होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(घ) परियोजना के पूर्ण होने पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में यात्री तथा माल परिवहन संपर्क को होने वाले संभावित लाभ क्या हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): नंगल डैम-तलवाड़ा-मुकेरियां का नंगल डैम-दौलतपुर चौक-करटोली पंजाब खंड (70 कि.मी.) कमीशन कर दिया गया है। करटोली पंजाब-मुकेरियां (52 कि.मी.) में निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। खंड-वार प्रगति निम्नानुसार है:

खंड	स्थिति
दौलतपुर चौक-करटोली पंजाब (10.5 कि.मी.)	कमीशन कर दिया गया है।
करटोली पंजाब-तलवाड़ा (13.65 कि.मी.)	01 बड़े पुल पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 07 छोटे पुलों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया हैं। 02 ऊपरी सड़क पुलों पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। 08 में से 06 निचले सड़क पुलों पर निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा शेष पुलों पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।
तलवाड़ा-मुकेरियां (28.70 कि.मी.)	15 बड़े पुलों पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। 40 में से 34 निचले सड़क पुलों पर निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष पुलों पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

	3 में से 2 स्टेशन भवनों पर निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष स्टेशन भवनों पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।
पटियाल-भंगाला (9.89 कि.मी.)	02 बड़े पुलों पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। 1 निचले सड़क पुल पर निर्माण कार्य शुरू किया गया हैं।

मार्च, 2026 तक परियोजना पर ₹2,724 करोड़ का व्यय किया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2026-27 में ₹800 करोड़ का आबंटन किया गया है।

पंजाब:

रेल बजट:

पंजाब में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं तथा संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹225 करोड़ प्रतिवर्ष
2026-27	₹5,673 करोड़ (25 गुना से अधिक)

रेलपथ निर्माण:

पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की प्रतिवर्ष औसत कमीशनिंग
2009-14	147 कि.मी.	29.4 कि.मी. प्रतिवर्ष
2014-26	391 कि.मी.	32.6 कि.मी. प्रतिवर्ष

स्वीकृत परियोजनाएं:

01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, पंजाब में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 745 कि.मी. कुल लंबाई तथा ₹24,708 करोड़ लागत वाली 11 परियोजनाएं (06 नई लाइन तथा 05 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई	कमीशन की गई लंबाई	मार्च, 2026 तक व्यय (₹ करोड़ में)
नई लाइन	06	283	75	9,246
दोहरीकरण/मल्टी-ट्रैकिंग	05	462	80	1,631
कुल	11	745	155	10,878

हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाएं:

पंजाब में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूर्ण की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (₹ करोड़ में)
1	चक्की बैंक-भरोली दोहरीकरण (3 कि.मी.)	15
2	जाखल-मानसा दोहरीकरण (45 कि.मी.)	163
3	मीरथल-भंगाला ब्यास नदी दोहरीकरण (2.5 कि.मी.)	74
4	अंबाला-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 कि.मी.)	339
5	मानसा-बठिण्डा दोहरीकरण (49 कि.मी.)	216
6	अमृतसर-छेहरटा दोहरीकरण (7 कि.मी.)	31

7	जालंधर-जम्मू तवी दोहरीकरण (209 कि.मी.)	850
8	कठुआ-माधोपुर पंजाब दोहरीकरण (2.5 कि.मी.)	257
9	राजपुरा-बठिण्डा दोहरीकरण (173 कि.मी.)	2,459

चालू परियोजनाएं:

पंजाब में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें शुरू किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (₹ करोड़ में)
1	नंगल डैम-मुकेरियां नई लाइन (123 कि.मी.)	3,726
2	भानुपल्ली-बेरी नई लाइन (63 कि.मी.)	13,770
3	कादियां-ब्यास नई लाइन (40 कि.मी.)	842
4	फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 कि.मी.)	764
5	रामा मंडी-मौड़ मंडी नई लाइन (29 कि.मी.)	154
6	लुधियाना-किला रायपुर दोहरीकरण (19 कि.मी.)	260
7	लुधियाना-मुल्लांपुर दोहरीकरण (21 कि.मी.)	359
8	राजपुरा-मोहाली नई लाइन (18 कि.मी.)	443
9	राजपुरा बाईपास लाइन (14 कि.मी.)	412

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी):

निजी निवेश के माध्यम से कार्गो टर्मिनलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति प्रारंभ की गई है। जीसीटी का स्थान उद्योग की मांग, कार्गो यातायात की क्षमता, रेल अवसंरचना की उपलब्धता तथा इस क्षेत्र की लॉजिस्टिक क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अब तक, 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) चालू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 310 अन्य स्थानों पर जीसीटी के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जा चुके हैं। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश में जीसीटी की स्थापना के लिए उद्योग जगत से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******